शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

शिक्षक भर्ती...29 जून से शुरू हो सकेगी सत्यापन की प्रक्रिया, 1 सितंबर तक स्कूलों में पहुंचेंगे नए शिक्षक

लोक शिक्षक संचालनालय ने तैयार की योजना, जिला शिक्षा अधिकारियों से होगी चर्चा

भास्कर न्यूज | भोपाल

स्कूल शिक्षा विभाग लॉकडाउन के कारण बंद की गई उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर रहा है। 29 जून से उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके लिए सभी तरह की कार्रवाई कर 1 सितंबर तक सभी चयनित शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त करने की योजना है। फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आवागमन की असुविधा से एक भी उम्मीदवार छूटता है तो भविष्य में परेशानी हो सकती है।

लोक शिक्षक संचालानालय के संचालक गौतम सिंह ने बताया कि 29 जून से सत्यापन प्रक्रिया को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों के बुधवार को बैठक कर रहे हैं। कोविड-19 से बचाव को लेकर उनसे चर्चा की जाएगी। उन्हें सुविधा दी जाएगी कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखकर सत्यापन केंद्र तय करने के लिए एक बार फिर से विचार कर लें। यदि कोई केंद्र कंटेंटमेंट एरिया में है तो उसे अन्य किसी स्थान पर शिफ्ट कर लें।

सत्यापन के लिए 5 जून से जिले में परिवर्तन कर सकेंगे उम्मीदवार...

लोक शिक्षण संचालनालय ने सीधी भर्ती के तहत प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों दस्तावेज अपलोड करने और पूर्व में अपलोड किए गए दस्तावेजों में हुई त्रुटि में सुधार करने का मौका दिया है। इसके साथ उम्मीदवार सत्यापन के लिए पहले चुने गए जिले में भी अपनी सुविधा के अनुसार परिर्वतन करा सकते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 5 से 12 जून और माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 10 से 24 जून तक उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं।

सुरक्षा पहली प्राथमिकता, उम्मीदवारों को तय स्लॉट में बुलाया जाएगा...

लॉकडाउन से पहले अभियान स्वरूप भर्ती पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अब उम्मीदवारों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी। इसलिए उन्हें उनके द्वारा चुने गए जिले में एक निर्धारित स्लॉट में बुलाया जाएगा। इसके लिए करीब 2 घंट का एक स्लॉट रहेगा। जिससे सोशल डिस्टेंटिंग का पालन हो सके। उन्होंने बताया कि परिस्थितियों को देखकर कुछ बदलाव किया जा सकता है।

स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो ताकि उम्मीदवारों को समय मिल सके...

आनंद मिश्रा का कहना है कि प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाएगा। विभाग भर्ती प्रक्रिया में अधिक समय न लगाए और स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों की नियुक्ति की कर दी जाए। इसके लिए पूरा शेड्यूल और स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जाए। ताकि उम्मीदवार तैयार रह सकें। स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक के 15 हजार और माध्यमिक शिक्षक के 5670 पद के लिए भर्ती अटकी है।

5 जून से शिक्षक पद के अभ्यर्थी अपलोडेड दस्तावेजों में कर सकेंगे सुधार

सतना। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पदों की सीधी भर्ती के तहत प्रावधिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के लिये दस्तावेज अपलोड करने अथवा पूर्व में अपलोड किये दस्तावजों में हुई त्रुटि में सुधार करने अथवा सत्यापन के लिये पूर्व में चयनित जिले में परिवर्तन की सुविधा एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर क्रमशः 5 से 12 जून तक तथा 10 से 24 जून तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार उक्त तिथियों में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं।

जब विषय पद नहीं है तो फिर अतिथि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे

विभाग के तर्कों पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल विसंगति की तत्काल जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री चौहान को पत्र

भोपाल। प्रदेश में लॉक डाउन के बीच माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा की भर्ती कराने जा विभाग की प्रक्रिया पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। मामला पदों की कमी का है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग के तर्कों के अनुसार पद नहीं है तो आखिर प्रदेश भर में अतिथि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पदों की जांच कराने की मांग की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया इसलिए सवालों के घेरे में है। क्योंकि हिंदी उर्दू संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के पद हजारों में होने के बावजूद विभाग ने भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर कटौती की है।

इनका यह भी आरोप है कि भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी की गई है वह पूरी तरह विसंगति पूर्ण है। जब प्रदेश में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, उर्दू के पद ही नहीं थे तो फिर इन विषयों की परीक्षा ही क्यों ली। या उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ बड़ा मजाक है। विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि यह विषय तो कोई ही पढ़ा सकता है। अधिकारी यह भी बता रहे है कि इन विषयों के जयादा पद नहीं है। सवाल उठाए हैं कि जब पद नहीं है फिर अतिथि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। प्रदेश में गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों की सख्त जरूरत है। इस कारण इन विषयों के पदों को भरने पर जोर दिया जा रहा है।

पदों के वितरण में हुई है भारी असमानता

सफल उम्मीदवार ममता निगम का कहना है कि पदों के वितरण में विभाग ने बड़ी असमानता की है। 100ए 50ए 60 ये पद हैं, हिंदी,सामाजिक विज्ञान के। ये तो विभाग के अधिकारी बिना परीक्षा लिए किसी से भी पढ़वा लेते। सामाजिक विज्ञान,विज्ञान,हिंदी के उम्मीदवारों के साथ, शिक्षा विभाग ने पदों का असमान वितरण करए अन्याय किया है। ऐसे में शिक्षक पात्रता परीक्षा .2018 का औचित्य ही क्या। उन्होंने कहा कि जब इन विषयों के पात्र उम्मीदवारों को अवसर ही नहीं दिया गया! इससे तो अच्छा है की विभाग को इन तीनों विषयों को पाठ्यक्रम से ही हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 10 वर्षों बाद परीक्षा हुई उसके बावजूद विषय पदों की भर्ती में भेदभाव कही ना कही शैक्षणिक स्तर को गिराने की साजिश है।

मुख्यमंत्री को तत्काल जांच करना चाहिए

सफल उम्मीदवार विष्णु सिंघानिया का कहना है कि भारती की जो विसंगतियां हैं उसकी तत्काल मुख्यमंत्री को जांच करवाना चाहिए। प्रदेश में लगभग 3 लाख हिंदी, संस्कृत सामाजिक विज्ञान,विज्ञान, उर्दू के योग्य बेरोजगार उम्मीदवार जो आशा संजोए हुए थे उन पर पानी फेर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई ,कोचिंग, बुक्स, परीक्षा फीस, गांव से आकर शहर में किराए भाड़े से रहना, अपनी 10,15 हजार रूपए महीने की नौकरी छोड़ कर परीक्षा दी थी। क्योंकि 10 वर्ष बाद भर्तियां निकली थी लेकिन इस प्रक्रिया में एक बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है।

शिक्षा अधिनियम के मापदंडों का नहीं रखा ख्याल

सफल उम्मीदवार रंजीत गौर का कहना है कि इस प्रक्रिया में आरटीई के मापदंडों का ख्याल नहीं रखा गया है। इस कारण हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को प्रतिवर्ष योग्य शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के माध्यम से करना चाहिए। परीक्षा से पहले ही अनुमानित पद स्पष्ट करना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब 10 साल वाद परीक्षा हुई है तो हर विषय के 5000 पद सरकार सुनिश्चित करे। जिससे सभी योग्य, पास अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके जिसके वो हकदार है। उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया में सरकार बाहर के अभ्यर्थियों का निश्चित कोटा तय करें।

स्कूलों को खोलने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार किया ब्लू प्रिंट, सरकार को भेजा

सितंबर से पहले शुरू हुआ सत्र तो छुट्टियां कम कर कोर्स करेंगे पूरा, बाद की स्थिति में कोर्स में भी होगी कटौती

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

चार लॉकडाउन के बाद अब देश में शुरू हुआ अनलॉक 1 शुरू हो गया है। हालांकि अभी शैक्षणिक संस्थानों को लेकर कोई निर्णय नहीं होने से स्कूलों के एक बार फिर खुलने को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा विभाग ने एक ब्लू प्रिंट तैयार किया है। विभाग ने इसे सरकार को भेजा है। इस ब्लू प्रिंट के मुताबिक यदि एक सितंबर के बाद सत्र शुरू किया गया तो सभी कक्षाओं के कोर्स में कटौती करनी होगी। इसके साथ ही स्कूलों को खोलने को लेकर तीन तारीखें भी सुझाई गई हैं कि यदि 15 जुलाई, 1 अगस्त व 15 अगस्त तक भी सत्र शुरू हो जाता है तो छुट्टियां खत्म कर एक्स्ट्रा क्लास लगाकर कोर्स पूरा करा लिया जाएगा। इसके लिए दशहरा, दीपावली के साथ सर्दियों व अन्य छुट्टियां खत्म की जाएंगी।

एक घंटे अधिक किया जाएगा स्कूल का समय

स्कूलों का समय एक घंटे अधिक किया जाएगा, इसमें हर क्लास की एक्स्ट्रा क्लास लगाकर कोर्स पूरा करवाया जाएगा। इसके साथ ही दो प्री-बोर्ड के बजाय एक प्री बोर्ड एग्जाम ही लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लू प्रिंट के अनुसार सितंबर और देर से शुरू होने पर जनवरी तक पूरा कोर्स तैयार करने का टारगेट रखा गया है। हालांकि विभागीय अधिकारी फिलहाल इस मामले में बोलने से बच रहे हैं और इसे इंटरनल प्रोसेस बता रहे हैं।

छुट्टियां 18 दिन के बजाए 8 दिन होंगी

सितंबर के पहले वाली तारीखों में सत्र शुरू हुआ तो दशहरा, दीपावली व सर्दियों की छुट्टियां 18 दिन के बजाय 8 दिन की जाएंगी। पिछले वर्ष से 10वीं-12वीं के जनवरी व फरवरी में दो प्री बोर्ड एग्जाम शुरू किए गए थे, उसके स्थान पर पूर्वानुसार एक ही प्री.बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा।

विभाग द्वारा की जा रही है तैयारी

यह इंटरनल प्रोसेस है। तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि जुलाई में स्कूल खुलने पर निर्णय होना है। उस हिसाब से विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है।

रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग

14 जून को देशभर की पैरेंट्स एसोसिएशन करेंगी स्कूल खुलने का विरोध

आल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन पैरेंट्स के बैनर तले देशभर के पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा मंगलवार को सरकारों के स्कूलों को खोलने के प्रयास, ट्यूशन फीस के नाम पर स्कूलों द्वारा किए जा रहे शोषण और ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में चर्चा की गई। इस आनलाइन मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जब तक कोरोना संक्रमण का निराकरण नहीं होता तब तक स्कूल नहीं खोले जाएं। अगर स्थिति काबू में नहीं आती तो इस वर्ष को शून्य वर्ष घोषित किया जाए। पालकों ने कहा कि हमारे बच्चे हमारी पूंजी है हम उन पर प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकते हैं। सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनलॉक अभियान चलाया गया है। स्कूल व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है। इसलिए इन्हें खोलने की कोशिश का हम पुरजोर विरोध करेंगे। एसोसिएशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 14 जून को पूरे देश में एक साथ शासन के निर्णय का विरोध किया जायगा और माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मानव संसाधन मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जायगा।

सम-विषम के आधार पर खुलेंगे स्कूल

शिक्षा विभाग ने तैयार की योजना

भोपाल

कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में अभी सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं। इन्हें कब से खोला जाए, यह निर्णय लिया जाना है। संक्रमण बढ़ने के कारण तिथि तय नहीं हो पा रही है। जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी है। उससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों को स्कूल बुलाने में ऑड-ईवन फॉर्मूला अपनाने जा रहा है। यानि सारे बच्चे एक साथ स्कूल नहीं आएंगे, बल्कि उन्हें एक दिन के अंतर से बारी-बारी बुलाया जाएगा।

कोरोना के कारण स्कूलों में व्यवस्था भी बदलने वाली है। पहले की तरह अब एक साथ सारे बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे। उन्हें भी ऑड-ईवन के मुताबिक बुलाने की तैयारी है। एक दिन प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या आधी होगी। आधे बच्चों को एक दिन और शेष को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। संक्रमण से बचाने के लिए एक साथ कम छात्र बुलाने की तैयारी है, ताकि उन्हें शारीरिक दूरी के साथ बैठाया जा सके। अगर पहले की तरह सारे बच्चे एक साथ सटाकर बैठाए जाएंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा।

कक्षा में शारीरिक दूरी का पालन जरूरी

प्रदेश भर के स्कूलों में छात्र छात्राओं के बीच शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। स्कूलों में अब तक एक बेंच पर तीन छात्र एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। अब बैठक व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है।

छात्रों को मास्क लगाना होगा

स्कूल में भी बच्चों को पूरे समय मास्क लगाना होगा। इसके बिना उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्रों के साथ शिक्षकों के लिए भी मास्क अनिवार्य होगा। हर कक्षा के बाहर सेनेटाइजर रखना होगा। बच्चों को कक्षा में जाने और कक्षा से बाहर आते समय अपने हाथों को सेनेटाइज़ करना होगा। हाथों को सेनेटाइज़ करने के बाद ही एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला नियम विरुद्ध की जा रही नियुक्तियां

मुंगावली बीआरसीसी में बीएसी के सभी स्वीकृत पद भरे होने के बाद भी डीपीसी ने कर दी नियुक्ति

- निज संवाददाता -

मुंगावली। छात्रों को हमेशा शिक्षा व नियमों का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षा विभाग हमेशा ही नियमों को लेकर विवादों में रहा है और एक बार फिर डीपीसी कार्यालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें भ्रष्टचार की बू आ रही है।

दरअसल, बीआरसीसी कार्यालय मुंगावली में बीएसी के कुल 5 पद स्वीकृत है और 5 पदों पर बीएसी कार्य कर रहे हैं। लेकिन डीपीसी श्री शुक्ला द्वारा नियमों को ताक पर रखते हुए यहां एक अतरिक्त बीएसी की नियुक्ति नियम विरुद्ध कर दी गई है। जब इस संबंध में डीपीसी से जानना चाहा तो वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और कहा कि मुंगावली बीआरसीसी को बोल दिया है कि यहां पदस्थ एक बीएसी को बीजीसी का चार्ज दे दिया जाए। डीपीसी का कहना है कि जिस बीएसी की नियुक्ति की गई है विद्यालय खुलते ही उसको मूल संस्था में भेज दिया जाएगा। लेकिन डीपीसी कुछ भी कहें नियमानुसार स्वीकृत पदों से ज्यादा नियुक्तियां करके कहीं न कहीं अपनी कार्यप्रणाली पर खुद ही सवाल खड़े कर लिए हैं।

डीपीसी कार्यालय।

बीआरसीसी बोले हमको नहीं कोई निर्देश:

अपने निजी स्वार्थों के चलते डीपीसी शुक्ला किस तह झूठ बोल रहे इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि जब डीपीसी से इस नियुक्ति के बारे में जानना चाहा तो उनके द्वारा कहा गया कि बीआरसीसी को एक बीएसी को हटाकर बीजीसी का चार्ज देने को कहा है। लेकिन जब बीआरसीसी से ऐसे किसी निर्देश या आदेश के बारे मे जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया गया कि हमको ऐसा कोई निर्देश व आदेश अभी तक नही मिला है सिर्फ बीएसी की नियुक्ति का आदेश है मिला है। आगे जो भी आदेश होगा उसके अनुसार कार्य कराएंगे। इन दोनों अधिकारियों के जबाबों को सुनकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि अपने चहेते शिक्षक को लाभ पहुँचाने के लिए डीपीसी द्वारा लगातार झूठ बोला जा रहा है।

बड़ा सवाल रिक्त पद पर क्यों नहीं की गई नियुक्ति ?

अधिकारियों द्वारा कहीं जा रही बातों के आधार पर बताया जा रहा है कि बीआरसीसी कार्यालय मुंगावली में बीजीसी का एक पद रिक्त था। जिसको बीएसी की नियुक्ति करके भरने का प्रयास मनमाने तरीके से डीपीसी द्वारा किया गया है। जबकि नियम पूर्वक देखा जाए तो जो पद रिक्त पड़ा था उसको भरना था न कि अपने चहेते को पुरस्कृत करके बीएसी को हटाकर बीजीसी का पद भरा जाएगा। पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद तो यही कहा जायेगा कि कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में न केवल अधिकारियों की मनमर्जी धड़ल्ले से चल रही है। बल्कि इनके आदेशों में भ्रष्टचार भी जमकर हो रहा है। अब देखना होगा कि इस तरह मनमर्जी पूर्वक डीपीसी द्वारा जो बीएसी की नियुक्ति की गई है उस पर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर इसी तरह नियमों को तांक पर रखकर शिक्षा विभाग इन अधिकारियों की मनमर्जी का शिकार होता रहेगा।

इनका कहना है:

'किस आधार पर नियुक्ति की गई है, डीपीसी को बुलाकर देखती हूँ और जानकारी लेती हूं। कोई भी नियुक्ति गलत तरीके नहीं की जाएगी।'

डॉ. मंजू शर्मा, कलेक्टर

अध्यापक संवर्ग का डाटा माइग्रेट करायें

रीवा। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी आरडी चौधरी ने समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि अध्यापक संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों को आईएफएमआईएस पोर्टल में माइग्रेट कर एम्पलाई कोड निर्मित किये जा चुके हैं। उपरोक्त अध्यापक संवर्ग का बेनिफिशरीज डिटेल जैसे बैंक एकाउंट, आईएफएमआईएस कोड, प्रान नंबर, एनपीएस आदि का सत्यापन आईएफएमआईएस एवं एनएसडीएल में करायें। माह मई पेड जून का वेतन संविलियन शिक्षक संवर्ग में लोक सेवकों के नवीन एम्पलाई कोड के आधार पर जनरेट कर आईएफएमआईएस द्वारा ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अध्यापकों को अब समय पर मिल सकेगा वेतन, एम्प्लाई कोड एलॉट

भा.सं.। रीवा। जिले के करीब एक हजार अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। इनके लिए लंबी प्रतीक्षा के बाद ट्रेजरी एम्पलाई कोड एलॉट कर दिया गया है। इससे अब उन्हें हर महीने न केवल समय पर वेतन का भुगतान हो सकेगा बल्कि सातवें वेतनमान के फिक्सेशन में भी उत्पन्न कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। इसका आदेश होते ही संबंधित अध्यापकों ने खुशी जताई है। बताया गया है कि पूर्व में ट्रेजरी एम्प्लाई कोड अध्यापकों को एलॉट न हो पाने से उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो पाता था। साथ ही सातवें वेतनमान के फिक्सेशन में दिक्कतें भी आ रही थी। एम्प्लाई कोड एलॉटमेंट के लिए कई बार संकुल के माध्यम से ईकेवाईसी करवाई गई। दस्तावेज जमा कराए गए। लेकिन एम्पलाई कोड एलॉट नहीं हो पा रहे थे। इस संबंध में अध्यापकों का कहना है कि संबंधित अधिकारी भी इस दिशा में गंभीर नजर नहीं आ रहे थे। अध्यापक हित में उनकी रुचि नहीं देखी गई। लेकिन नवागत बीईओ केपी तिवारी के पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन मंगलवार को रीवा विकासखण्ड के करीब एक हजार अध्यापकों का एम्पलाई कोड एलॉट कर दिया गया। अन्य विकासखण्डों में एम्पलाई कोड एलॉट किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। इस संबंध में बीईओ केपी तिवारी ने बताया कि रीवा विकासखण्ड के सभी अध्यापक सूची का अवलोकन करें जिनके नाम सूची में नहीं हैं या जिनकी केवाईसी पूरी नहीं हो पाई है वह दस्तावेजों के साथ संकुल प्राचार्य के माध्यम से विकासखण्ड रीवा में संपर्क कर अपनी औपचारिकताएं पूरी करा सकते हैं। बीईओ केपी तिवारी ने संकुल प्राचार्यों से कहा है कि अध्यापकों के एम्प्लाई सूची से नाम नोट कर लें जिससे एनआरसी की प्रक्रिया में दिक्कतें न आएं।

पहली से बारहवीं तक का पच्चीस फीसदी तक कम हो जाएगा सिलेबस

एनसीईआरटी ने गाइड लाइन की तैयार अगले सप्ताह तक स्कूलों में जाएगी

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

कोरोना संकट को देखते हुए सीबीएसई स्कूलों में पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों का पच्चीस से तीस फीसदी सिलेबस कम हो जाएंगे। एनसीईआरटी ने इसके लिए गाइड लाइन तैयार कर ली है। अगले सप्ताह तक स्कूलों में भेजी जाएगी। कोरोना संकट के लॉकडाउन के कारण लंबे समय बच्चे घरों में कैद है। अभी नवीन शैक्षणिक सत्र को लेकर कयास ही लगाए जा रहे है। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने और अचानक से बच्चों पर सिलेबस का बोझ न पड़े, इसके लिए हर क्लास के हर सब्जेक्ट से तीन से चार चैप्टर कम किए जाएंगे। इसके लिए एनसीईआरटी की गाइडलाइन अगले सप्ताह में स्कूलों में भेजी जाएगी। इस तरह पहली से बारहवीं तक का सिलेबस 25 से 30 फीसदी तक कम किया हो जाएगा।

जुलाई में लिया जाएगा स्कूल खोलने का निर्णय : एमएचआरडी की गाइडलाइन के अनुसार जुलाई में स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। पंद्रह अगस्त के बाद या फिर सितंबर से स्कूल खोलने की घोषणा हो सकती है। ऐसे में अभी तक लगभग दो सौ दिन पढ़ाई होती थी, वह मात्र 130 या 140 दिन ही हो पाएगी। सेशन में कम समय के मिलने कारण कोसज़ भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने कोर्स कम करने का निणज़्य लिया है।

सेकंड व थर्ड टर्म से हटेंगे चैप्टर : इसके तहत सेकंड और थर्ड टर्म के सिलेबस में कई चैप्टर हटाए जाएंगे। सिलेबस में बचे शेष चेप्टरों के आधार पर एग्जाम होंगे। स्कूल खुलने पर फर्स्ट टर्म होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। सेकंड और थर्ड टर्म की पढ़ाई बदले हुए चैप्टर के अनुसार होगी।

विद्यार्थियों को मिलेगी प्रिंटेड वर्कशीट

क्लास की पढ़ाई अधिक से अधिक हो, इसके लिए कक्षा में दी जाने वाली होमवर्क नोट सिस्टम को बदला जा रहा है। होमवर्क नोट लिखने की जगह स्टूडेंट्स को प्रिंटेंड वर्कशीट दी जाएगी।

अभी तक स्कूलों में करीब दौ दिन से ज्यादा पढ़ाई होती थी। अभी स्कूल खुलने की तिथि तय नहीं है। अब स्कूल खुलेंगे, तो 130 से 140 दिन ही पढ़ाने के लिए मिलेंगे। इसलिए 25 से 30 फीसदी सिलेबस कम करना आवश्यक है। एनसीईआरटी द्वारा सिलेबस कम किया जा रहा है, गाइडलाइन का इंतजार है।

डा. राजेश शर्मा, चेयरमैन, सीबीएसई स्कूल सहोदय ग्रुप

अतिथि विद्वानों ने की नियमितीकरण की मांग

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

मध्यप्रदेश में कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन हटते ही विगत करीब पांच माह से अधिक समय से राजधानी के शाहजहांनी पार्क में धरने पर बैठे अतिथि विद्वानों ने सरकार से एक बार फिर से उनका नियमितीकरण करने एवं लोक सेवा आयोग की इस विवादित परीक्षा की उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग उठा दी है।

मंगलवार 2 जून को मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में अतिथि विद्वानों ने मांग की है कि प्रदेश में लगभग 1800 अतिथि विद्वान/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी फालेन आउट हैं। विगत 6 माह से फालेन आउट होकर बेरोजगारी के इस दुःख को न सह पाने के कारणे 4 अतिथि विद्वान साथी मौत को गले लगा चुके हैं। आज उनका परिवार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज भी बहुत सारे फालेन आउट साथी भारी तनाव में हैं। इस तरह इनके और इनके परिवार के जीवन को सरकार बचाए और जिससे दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह भदौरिया का कहना है कि ज्यादातर अतिथि विद्वान साथी 45 से 55 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं। अब हम सब अपने परिवार की जिम्मेदारी एवं बच्चों के भरण पोषण के लिए कहां जाएंगे। इस कारण अतिथि विद्वान परिवार अब आप के भरोसे आस लगाए हैं। अब उन पर दया दिखाकर नियमित करने की कृपा करें। हमारा सम्पूर्ण परिवार आपको दिल से दुआ देगा। सदैव आपका ऋणी रहेगा।

निःशक्त विद्यार्थियों की शेष परीक्षाएं 9 जून से

भोपाल। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि :शक्तजन कल्याण श्रीमती रेनु तिवारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं की शेष बची परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाए 9 जून से 16 जून 2020 तक संचालित होगी। परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट www.socialjus-tice.mp.gov.in पर और विभाग के फेसबुक पेज पर भी अपलोड किया गया है। श्रीमती तिवारी ने बताया कि नि : शक्त छात्र-छात्राओं के लिये परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि कोविड-19 के लिये जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा केन्द्रों में आये। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अनिवार्य रूप से पहने। श्रीमती तिवारी ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर सहायक शिक्षकों को दी जाए जगह

बैरसिया। राज्य सरकार उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रही है। उक्त संदर्भ में शिक्षक संघ की ओर से मांग की गई है कि उक्त रिक्त पदों की पूर्ति सहायक शिक्षक और शिक्षकों को उनकी योग्यता एवं वेतनमान के आधार पर की जाए। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आयेगा और शिक्षकों की कमी भी पूर्ण होगी। मप्र तृतीय वर्ग शा.कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक अरविन्द भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि संघ की ये वर्षों पुरानी मांग है। संघ के प्रतिनिधि मंडल को शासन द्वारा अनेक बार आश्वासन दिया जा चुका है, परंतु अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण शिक्षकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। श्रीवास्तव का कहना था कि इससे हजारों शिक्षक लाभान्वित होंगे जो एक ही पद पर अपनी 32 से 40 वर्षों की सेवाएं दे रहे हैं। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश नारायण सक्सेना, सुधीर कलसे ,कैलाश धौलकर, अरुण पुरोहित, अमित सेंगर, सरोज वाला शर्मा, संध्या तिवारी, सुचि श्रीवास्तव,माधुरी पांडे,अजय गवली, अखिलेश चौदह, जितेंद्र चौहान ,मनोज कुमार शर्मा,राजेंद्र सर,अजीत सिंह, राजेश उपाध्याय, महेश शर्मा,आदि सभी पदाधिकारियों द्वारा शासन से उनकी इस समस्या को निराकरण कर पदनाम देने की मांग की गई है।

50 प्रतिशत स्टाफ के साथ शुरू हो सकती हैं ऑनलाइन कोचिंग

भोपाल। जिला प्रशासन अनलॉक-1 में रियायत देने की तैयारी कर रहा है। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का अध्ययन हो रहा है। इसमें 8 जून से खोले जा ऑनलाइन कोचिंग पर विचार चल रहा है। इसके तहत कोचिंग स्थान अपने 50 प्रतिशत स्टाफ को बुलाकर विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस लेकर उनका सिलेबस पूरा करा सकता है। इसमें शिक्षक कोचिंग पहुंचकर लेक्चर देकर नोट्स तैयार करा सकेंगे। ऑनलाइन क्लासेस होने से विद्यार्थियों को कोचिंग तक नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह धार्मिक स्थलों के लिए अलग से विचार मंथन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि संक्रमित क्षेत्रों के साथ शहर में धार्मिक स्थलों को लेकर कुछ नियम बनाए जा सकते हैं।

तनावग्रस्त बच्चों को उपलब्ध होगा मनोसामाजिक परामर्श

भोपाल। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण बच्चों में मानसिक तनाव एवं व्यग्रता आदि की समस्याएं देखने में आ रही हैं। महिला-बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों और अभिभावकों को सलाह एवं परामर्श देने के लिए चाइल्ड लाईन सेवा 1098 के अतिरिक्त जिला स्तर पर विशिष्ट टेलिफोनिक सायको सोशल हेल्थ डेस्क स्थापित किए गए है। यूनीसेफ एवं निमहेन्स बेगंलुरू के सहयोग से प्रत्येक जिले के लिए प्रशिक्षित मनो सामाजिक परामर्श दल तैयार किए हैं।

सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी को हेल्थ डेस्क का प्रभारी बनाया गया है। महिला-बाल विकास विभाग द्वारा केन्द्रीकृत नम्बर 8889983062, 6205397158 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सोमवार से शनिवार परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था आमजन के लिए की गई है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घरों पर सुरक्षित रखने, उन्हें रुचि अनुसार रचनात्मक कार्यों में संलग्न रखने और ऑनलाईन अध्ययन करने जैसे परामर्श अभिभावकों को हेल्थ डेस्क द्वारा दिए जा रहे हैं।

निजी स्कूलों से नोटिस दिए बिना ही निकाला जा रहा है टीचर्स को

कलेक्टर से की गई शिकायत, डीईओ ने शुरू की जाँच

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

राज्य सरकार के आदेश के बावजूद निजी स्कूलों ने बड़ी संख्या में टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को बिना नोटिस नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। मंगलवार को नौकरी से निकाली गई एक टीचर ने कलेक्टर से शिकायत की है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिकायत की जाँच शुरू कर दी है।

स्मॉल वंडर स्कूल बल्देवबाग की एक टीचर ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि मंगलवार दोपहर स्कूल से उसके पास कॉल आया कि उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी हैं। उनके स्कूल से अभी तक 70 से अधिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को नौकरी से निकाला जा चुका है। नौकरी से निकालने के पहले नोटिस भी नहीं दिया गया। टीचर ने बताया कि स्कूल ने सभी टीचरों और नॉन टीचिंग स्टाफ से पूरे अप्रैल महीने काम कराया था, लेकिन उन्हें आधी सैलेरी दी गई थी। टीचर ने अपनी शिकायत में कहा है कि आदित्य कॉन्वेन्ट स्कूल और ज्ञान गंगा स्कूल से भी बड़ी संख्या में टीचरों को नौकरी से निकाला गया है। शिकायत में कलेक्टर से अनुरोध किया गया है कि प्लीज हमारी सहायता कीजिए, भविष्य बनाने वालों का भविष्य अंधकार में है। इस मामले में पक्ष लेने के लिए ज्ञान गंगा स्कूल के प्राचार्य को कई बार फोन लगाया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।

स्मॉल वंडर स्कूल की एक टीचर ने कलेक्टर से नौकरी से निकाले जाने की शिकायत की है। कलेक्टर के निर्देश पर शिकायत की जाँच की जा रही है। जाँच रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सुनील नेमा, डीईओ, जबलपुर

हर साल एग्रीमेंट समाप्त होने पर कुछ टीचरों की सेवाएँ समाप्त की जाती हैं। स्कूल से ऐसे एक या दो टीचरों को निकाला गया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। स्कूल से बड़ी संख्या में टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को नहीं निकाला गया है।

संगीता ग्रोवर, प्राचार्य, स्मॉल वंडर स्कूल

केवल उन टीचरों को नौकरी से निकाला गया है, जिनका एग्रीमेंट समाप्त हो गया था। फिलहाल किसी भी टीचर को नौकरी से नहीं निकाला गया है।

दिव्या बाजपेयी, प्राचार्य
आदित्य कॉन्वेन्ट स्कूल

हायर सेकेण्डरी के साधन विहीन परीक्षार्थियों को वाहन की सुविधा दी जाएगी

पन्ना। कन्टेनमेंट ग्रामों के भ्रमण के दौरान 09 जून से 16 जून तक हायर सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के शामिल होने की समस्या की जानकारी दी गयी। कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा बताया कि परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने के लिए शासन द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर ली जाए जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। उनके लिए वाहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जिन परिवारों के पास अपने स्वयं के वाहन है वे परीक्षार्थी अपने स्वयं के वाहन से समय पर परीक्षा केन्द्र जा सकते हैं।

केंद्र अध्यक्षों को परीक्षा केंद्र सेनिटाइज कराने के निर्देश

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं के शेष पेपरों की परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भोपाल के सभी 97 परीक्षा केंद्र अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। बैठक में परीक्षार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा केंद्र का सेनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने सहित 6 फीट डिस्टेंस के हिसाब से बैठक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

शिक्षक पहुंचे एसपी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी बेखबर

केसी जैन कॉलेज व स्कूल में अराजकता का भंडाफोड़

सतना। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की मान्यता देने वाली समिति की मनमानी और दूरदर्शिता के चलते छात्र-छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कई ऐसे कॉलेज और स्कूल हैं जहां पर अराजकता का माहौल है। मंगलवार को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कामता टोला इलाके में स्थित केसी जैन कॉलेज और जैन बाल विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बदइंतजामी और अराजकता का भंडाफोड़ करते हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं का दल पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल के कार्यालय पहुंचा। जहां उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई।

ऐसा है शिक्षा का मंदिर

पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल को सौंपे गए शिकायती पत्र में विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बताया है कि केसी जैन कॉलेज कामता टोला सतना एवं जैन बाल विद्या मंदिर उत्तर माध्यमिक विद्यालय एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं जिसमें दोनों संस्थाओं में अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति है यह पूर्ण तहत गैरकानूनी है। शिकायत में बताया गया है कि दोनों संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को विगत 6 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। महाविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ तथा प्रयोगशाला विहीन है, खेल मैदान जो दिखाया गया है वह पूरी तरीके से फर्जी यानी की जाली है। साथ ही मान्यता के लिए जो लीज लगाई गई है वह 30 वर्ष के लिए है परंतु उसे फर्जी कूट रचित तरीके से 80 वर्ष दिखाया जा रहा है। शिकायत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मान्यता में लगाया गया नक्शा एवं अन्य दस्तावेज पूरी तरह के से फर्जी और जाली है। कर्मचारियों द्वारा वेतन मांगने पर संचालक गौरव जैन और प्राचार्य मीनू जैन द्वारा धमकाया एवं भविष्य नष्ट करने की धमकी दी जाती है।

पुलिस से फरियाद

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन सौंपने गए आधा दर्जन शिक्षक और शिक्षिकाओं ने आवेदन देने के साथ-साथ उन्हें बहुत सारी जानकारी भी अवगत कराइ, और यह भी कहा

गया है कि आवेदन के आधार पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि सभी को न्याय मिल सके। ज्ञापन में उम्मीद जताई गई है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी।

कोई जानकारी नहीं : डीईओ

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह ने हरिभूमि से बातचीत करते हुए कहा कि केसी जैन कॉलेज और जैन बाल विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में उनके पास कोई भी शिकायत नहीं है। विद्यालय को मान्यता दिए जाने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है जो रिकमेंड करती है उसके आधार पर विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि यदि मेरे पास कोई शिकायत आती है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

कराएंगे जांच : सीएसपी

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कॉलेज और स्कूल के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को मिली शिकायत के बाद नगर पुलिस अधीक्षक विजय सिंह परिहार को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। हरिभूमि से बातचीत करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक विजय सिंह परिहार ने कहा कि मामले को गंभीरता से जांच कराई जाएगी, तथा दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

विवादों में रहता है कॉलेज

उधर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक केसी जैन कॉलेज और स्कूल हमेशा विवादों में घिरा रहता है। एक ही बिल्डिंग में चलने वाले इस कॉलेज और स्कूल को कुछ दिन पहले किराए पर दिया गया था। जिस व्यक्ति ने इसे किराए पर लिया था वह व्यक्ति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ है। बताते हैं कि पहले तो सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा लेकिन जब पैसे की बात आई तो कॉलेज स्कूल के संचालक और जिसे किराया संस्थान दिया गया है उनके बीच कहासुनी हो गई, उसके बाद से विद्यालय और भी विवादित हो गया है। कुछ लोग दबी जुबान तमाम तरह की गतिविधियों की भी चर्चा करते हैं।

कंटेनमेंट जोन में निवासरत छात्रों के प्रवेश-पत्र को ही पास की मान्यता

सतना। हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2020 (सामान्य/दिव्यांग छात्र) की शेष विषयों की परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 9 से 16 जून 2020 तक कराये जाने के निर्देश जारी किये गए है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा निर्देश जारी किए हैं कि कंटेनमेंट जोन में निवासरत छात्रो के लिए परीक्षा केन्द्र में आने जाने हेतु छात्रो के प्रवेश पत्र को ही पास के रूप में मान्य किया जाय। माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2020 (सामान्य/दिव्यांग छात्र) की शेष विषयों की परीक्षाओं के आयोजन दिनांक 9 से 16 जून 2020 तक कक्षा 12वीं के छात्रो को मण्डल द्वारा जो प्रवेश पत्र जारी किये गए है। उन्ही प्रवेश पत्रो को निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र तक आने जाने के लिए पास के रूप में मान्य किया जावेगा तथा छात्रो के साथ एक अभिभावक को साथ में आने जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

स्कूलों में भी बनाए जाएँगे रादुविवि के परीक्षा केन्द्र

अधिकारियों और कर्मचारियों को परीक्षा की तैयारी में जुटने का आदेश

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर| रादुविवि में परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए 20 नए परीक्षा केन्द्र बनाए जा रहे हैं, इनमें से लगभग 10 परीक्षा केन्द्र स्कूलों में बनाए जाएँगे, इससे परीक्षा केन्द्रों की संख्या 71 से बढ़कर 91 हो जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में दी गई। बैठक में कुलपति प्रो. कपिलदेव मिश्र ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से परीक्षा की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। 8 जून से 33 प्रतिशत कर्मचारी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। बैठक में प्रभारी कुलसचिव डॉ. दीपेश मिश्रा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है।

यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जनरल प्रमोशन का विरोध - अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जनरल प्रमोशन का विरोध किया है। अभाविप के महानगर मंत्री सर्वम सिंह राठौर ने रादुविवि कुलपति को ज्ञापन सौंपकर बताया कि जनरल प्रमोशन की जगह परीक्षा कराने के लिए अन्य विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। पी-2

सीबीएसई की अधिसूचना जारी, स्कूलों में होगी परीक्षा

नई दिल्ली | सीबीएसई ने 10वीं (दिल्ली के उत्तर-पूर्व जिले) और 12वीं की परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जारी की है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षा के लिए दो बदलाव किए गए हैं। अब विद्यार्थी परीक्षा केंद्र की जगह अपने ही स्कूल में पेपर दे सकेंगे। वे अभी जिस जिले में हैं, वहीं का परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे।

बीआरसी कार्यालय हुआ क्षतिग्रस्त. जवाबदार अधिकारी नहीं ले रहे सुध

रामपुर बाघेलान, (नि.प्र.)। शासन द्वारा शिक्षा के महत्व को तो बताया जाता है मगर शिक्षा को व्यवस्थित रखने वाले अधिकारियों की जान खतरे में पड़ती नजर आ रही है जिसमें देखा जाए कि रामपुर बाघेलान के बीआरसी कार्यालय संचालित बिल्डिंग लगभग 60प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो चुकी है मगर कई बार अधीनस्थ अधिकारियों को लिखित सूचित किया गया और यह खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई मगर कई बार सूचित करने के बाद भी आज तक ना ही कार्यालय को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और ना ही विल्डिंग की मरम्मत पर ध्यान दिया गया।

देखा जाए तो जिस तरह से इस बिल्डिंग का हाल है आने वाले बरसात के समय में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें दर्जनों कर्मचारियों की जिंदगी का जवाबदार कौन होगा यह सोच से परे है समय रहते अगर बीआरसी कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है जिसका जवाबदार प्रशासन होगा।

परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर एक घंटा पहले उपस्थित होना होगा

दतिया ब्यूरो

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की स्थगित परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के क्रम में परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

जिलाधीश ने ली केन्द्राध्यक्षों की बैठक

मंगलवार को इस संबंध में जिलाधीश रोहित सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षाएं 9 से 16 जून तक दो पाली में प्रातः 9 से दोपहर 12 एवं अपरान्ह 2 से शाम 5 बजे तक होंगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को प्रातः 8 बजे तक और द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को एक बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8.45 एवं दोपहर 1.45 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर-पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न-पत्र दिए जाएंगे। हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम दृष्टि बाधित, मूक-बधिर (दिव्यांग), नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों की परीक्षाएं अपरान्ह 2 से 5 बजे तक होंगी। परीक्षा केन्द्र पर सभी छात्रों को अपने नाक और मुंह को नकाब अथवा कपड़े से ढंककर रखना और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।

अप्रैल में जिनका 400 रुपए से कम बिजली बिल आया है, उनका मई, जून, जुलाई का बिल होगा आधा

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रमुख सचिव उर्जा ने जारी किए निर्देश

अब नई बिल भुगतान व्यवस्था के तहत जमा होंगे बिल

नगर संवाददाता, भोपाल

लॉकडाउन के चलते प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बिजली बिलों के भुगतान में राहत दी है। दो दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। उनकी घोषणा के बाद उर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने तीन बिजली कंपनियों में इस व्यवस्था को लागू किए जाने के निर्देश मंगलवार को जारी कर दिए हैं। इसके तहत अप्रैल में जिनका बिजली बिल 100 से ज्यादा, लेकिन 400 रुपए कम आया है। उन्हें मई, जून-जुलाई में 400 रुपए से अधिक बिल आने पर भी आधा बिल जमा करना होगा। वहीं गैर-घरेलू, गैर-औद्योगिकी , निम्न दाव एवं उच्च दाव औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे - दुकानें, शोरूम, अस्पताल , रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग आदि के माह अप्रैल से जून तक के बिजली बिलों के फ़िक्स चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। यह राशि अक्टूबर 2020 मार्च 2021 के बीच 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों दुकानदारों छोटे व्यवसायियों की लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि आगामी महीनों में ली जाएगी।

ऐसे होगा बिलों का भुगतान		
अप्रैल का बिल	मई, जून, जुलाई का बिल	मई, जून, जुलाई में भुगतान
100 रुपए	100 रुपए	50 रुपए
100	100 से 400	100 रुपए
100 से 400 तक	400 से अधिक	आधा बिल

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ऐसे मिलेगा फायदा

- संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपए या उससे कम आये थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रूपए से कम आएंगे, उन्हें मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपए महीने का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रूपये का लाभ होगा।
- ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपए से कम आए थे, किन्तु मई, जून और जुलाई माह में 100 रुपए से अधिक परंतु 400 रुपए से कम आए हैं, या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपए प्रतिमाह का भुगतान करना होगा। इससे लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।
- ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपए से अधिक परन्तु 400 रूपए से कम आए थे, किन्तु मई, जून और जुलाई माह में रूपए 400 से ज्यादा आए हैं या आएंगे, तो उन्हें मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। शेष बिल की राशि की जांच के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। इससे लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। हितग्राहियों को लगभग 200 करोड का लाभ होगा।

26 दिन बाद परीक्षा, विवि अभी तक तैयार नहीं कर पाया प्रश्न पत्र

स्नातक अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की 29 से होनी है परीक्षा

जागरण, रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अभी तक स्नातक अंतिम वर्ष की मुख्य वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र नहीं बनवा सका है। राज्यपाल व उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार उक्त परीक्षा 29 जून से कराना है। फिर भी विश्वविद्यालय की तैयारी धीमी गति से चल रही है। गत 25 मई को विभाग के प्रमुख सचिव व आयुक्त ने जूम एप के जरिये भी परीक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस समीक्षा में सामने आया कि रीवा विश्वविद्यालय व बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को छोड़कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रश्न पत्र मुद्रण का कार्य हो चुका है। इस पर रीवा विश्वविद्यालय कुलपति ने परीक्षा पूर्व नियत समय पर प्रश्न पत्र मुद्रण कराने की बात अधिकारियों से कही है। यानि विश्वविद्यालय को स्नातक अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र निर्माण में और समय लगेगा।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस से फैल रही महामारी को नियंत्रित करने विगत 14 मार्च से शिक्षण संस्थान बंद हैं। उस समय ही विश्वविद्यालय ने गत 24 मार्च से परीक्षा कराने कार्यक्रम जारी किया था, परंतु लॉकडाउन होने के कारण तब परीक्षा स्थगित हो गई थी। इस परीक्षा में करीब 80 हजार छात्रों को शामिल होना था, जिनके लिए विश्वविद्यालय ने 71 परीक्षा केंद्र बनाए थे। इतना कुछ करने पर भी विश्वविद्यालय प्रश्न पत्र निर्माण की कार्यवाही अभी

पूरी नहीं कर पाया, जबकि पूरे लॉकडाउन की अवधि में राज्यपाल परीक्षा के लिए तैयार रहने के निर्देश विश्वविद्यालय को देते रहे। बता दें कि सत्र 2019-20 की इस परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरा लिए हैं।

छात्रों की लोकेशन पता करने जारी की लिंक

गत दिवस हुई समीक्षा में परीक्षार्थियों की लोकेशन पता करने पर भी चर्चा हुई है। ताकि कोई भी छात्र दूसरे जिले में होने की वजह से परीक्षा से वंचित न हो। इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन जानकारी एकत्रित करने एक लिंक जारी किया है। इस लिंक के माध्यम से महाविद्यालय प्राचार्य छात्रों के मौजूदा निवास क्षेत्र का ब्यौरा विभाग को देंगे। जूम एप के जरिये हुई समीक्षा में यह भी सुझाव दिया गया है कि जो छात्र इस परीक्षा से वंचित हो जायें, उनके लिए सितम्बर में विशेष परीक्षा कराने पर विचार किया जाये।

सुरक्षा को लेकर बरती जाये सावधानी

उक्त समीक्षा में उन परीक्षा केंद्रों को लेकर भी चर्चा हुई, जिन्हें लॉकडाउन की अवधि में कोरोना मरीजों के लिए कोरोनटाइन सेंटर बनाया जा चुका है। इस पर विभागीय अधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन से सम्पर्क कर नजदीकी अन्य दूसरे महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी विश्वविद्यालय द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों को शत-प्रतिशत सेनेटराइज कराने के लिए विभाग ने कहा है। साथ ही प्रत्येक पाली की परीक्षा उपरांत सेनेटराइज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा छात्रों को मास्क लगाकर परीक्षा में शामिल कराने के लिए कहा गया है। परीक्षा केंद्रों में भी कुछ मास्क की उपलब्धता रखने की हिदायत समीक्षा में दी गई है।

9वीं, 11वीं के अनुतीर्ण छात्रों को मिले पुर्नगणना आवेदन का मौका

रीवा। कक्षा 9वीं, 11वीं के अनुतीर्ण छात्रों को अब तक पुर्नगणना आवेदन की सुविधा नहीं मिली है। इस दिशा में सुधार करने सामाजिक कार्यकर्ता रोहिणी द्विवेदी ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र सौंपा है। पत्र में उन्होंने बताया कि सत्र 2019-20 की 9वीं, 11वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इसमें से जो छात्र पूरक रहे, उन्हें कोरोना महामारी आपदा के कारण शासन के निर्देश पर जनरल प्रमोशन देकर उत्तीर्ण कर दिया गया परंतु अनुर्तीण छात्रों के हित में कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया। जबकि शासन द्वारा अनुतीर्ण छात्रों के लिए भी पुर्नगणना का प्रावधान पहले से ही दिया गया है। इस बिंदु की तरफ डीईओ का ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र में उचित कार्यवाही की मांग की गई है।

कंटेनमेंट जोन बन चुके 4 परीक्षा केंद्रों को बदला

माशिमं ने नजदीकी दूसरे विद्यालयों को बनाया 12वीं की परीक्षा हेतु केंद्र

जागरण, रीवा। कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए जिले में चार परीक्षा केंद्र बदले गए हैं। कोरोना मरीजों के लिए कंटेनमेंट जोन बनने के कारण उक्त केंद्रों को बदलना पड़ा है। इस बाबत जिला कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। मार्च 2020 में 12वीं परीक्षा के दौरान शासकीय विद्यालय गोड़हर परीक्षा केंद्र बना रहा। इसी तरह ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, कटरा विद्यालय व खजुहा विद्यालय परीक्षा केंद्र बने थे, जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है। बताया गया कि जिन छात्रों का केंद्र गोड़हर विद्यालय में रहा, उनके लिए अब उमादत्त विद्यालय ढेकहा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसी प्रकार ज्ञानोदय विद्यालय के स्थान पर सेंट्रल एकेडमी स्कूल, कटरा विद्यालय के बदले शासकीय हाइस्कूल जमुई तथा खजुहा विद्यालय का केंद्र परिवर्तित कर लक्ष्मणपुर विद्यालय को नया केंद्र बनाया गया है।

गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं हमेशा की तरह नियत समय गत मार्च माह में प्रारम्भ हो चुकी थी परंतु कोरोना वायरस से फैल रही महामारी की रोकथाम हेतु तब परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। अब 10वीं के छात्रों को उत्तीर्ण करने की घोषणा माशिमं ने कर दी है। जबकि 12वीं के छात्रों की शेष विषयों की परीक्षा का कार्यक्रम माशिमं ने घोषित किया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 12वीं के शेष विषयों की परीक्षा 9 से 16 जून के बीच

होगी। इस परीक्षा में जिले के 24 हजार 273 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

1 घंटे पहले पहुंचना होगा केंद्र

माशिमं ने कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर 1 घंटे पूर्व उपस्थित होने के लिए कहा है। ताकि परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। आगामी परीक्षाएं दो पाली में होंगी। पहली पाली की परीक्षा प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। बताया गया कि प्रथम पाली के विद्यार्थियों को प्रात3 8 बजे तक तथा द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को दोपहर 1 बजे तक केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8.45 एवं दोपहर 1.45 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर-पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न-पत्र दिये जायेंगे। हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम दृष्टिहीन, मूक, बधिर (दिव्यांग), नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों की परीक्षाएं अपरान्ह 2 से 5 बजे तक होंगी।

मुंह ढंके, समूह न बनायें, सफाई का ध्यान रखें छात्र

बताया गया कि परीक्षा केन्द्र पर सभी छात्रों को अपने नाक और मुंह को नकाब अथवा कपड़े से ढंक कर रखना और फिजिकल डिस्टेंस नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा उपरांत छात्र समूह न बनायें। प्रयास करें कि अकेले या अपने परिजनों के साथ तुरंत घर पहुंचे और हाथ धुलाई जैसी अन्य सफाई का विशेष ध्यान रखें।

बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रावासों को कराना होगा सेनेटाइज

अपर कलेक्टर इला तिवारी ने नगर पालिक निगम के आयुक्त, जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षायें 9 जून से 15 जून तक संपन्न होनी है। कोविड-19 वायरस संक्रमण के चलते उक्त अवधि में छात्रावासों में सेनेटाइजेशन एवं फ्यूमिगेशन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय।

जेएलयू की मप्र में लगातार 5वीं बार नंबर 1 रैंकिंग

एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा जारी बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जेएलयू का भारत में 35वां स्थान

जागरण सिटी रिपोर्टर, भोपाल। एजुकेशन वर्ल्ड ने 2019-2020 के लिए ऑल इंडिया रैंकिंग जारी की है, जिसमें जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी को भारत की 334 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से 35वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। इस तरह से पूरे मध्य भारत में सभी यूनिवर्सिटी के बीच मध्यप्रदेश में लगातार 5वीं बार जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी ने नंबर वन यूनिवर्सिटी का स्थान हासिल किया है। ऑल इंडिया रैंकिंग में नियमित रूप से आगे बढ़ते हुए जेएलयू ने विशिष्ट रूप से एकेडेमिक एक्सीलेंस, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटरनेशनलाइजेशन में भी कदम बढ़ाया है। जागरण लेकसिटी

यूनिवर्सिटी की अपने सभी स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने की योग्यता और रिसर्च कार्य इसे प्रमाणित करते हैं। फिलहाल यहां 56 डिग्री प्रोग्राम हैं जिनमें 2500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 8 देशों और देश भर के 27 राज्यों के स्टूडेंट्स यहां शिक्षा ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा टॉप इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ 27 पार्टनरशिप्स की गई है, जिससे स्टूडेंट्स को नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर प्राप्त होगा। जेएनयू सेंट्रल इंडिया से यूरोपियन कमीशन से फंडेड ट्यूनिंग इंडिया प्रोजेक्ट के ERASMUS+ प्रोग्राम में भाग लेने वाली एकमात्र यूनिवर्सिटी है। ■ शेष पृष्ठ 7 पर

कैसे सुधरेगी देश की शिक्षा

देश के कई राज्यों में शिक्षा अतिथि शिक्षकों के भरोसे है। राजधानी दिल्ली के करीब 38 फीसद शिक्षक अतिथि की श्रेणी में आते हैं। आंकड़ों के पहाड़ से नीचे झांकें तो यही दिखाई देता है कि सिर्फ दिल्ली में 22 हजार अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अतिथि शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता। यह वह शिक्षक समुदाय है जो अपनी पूरी क्षमता और ऊर्जा लगाता है, लेकिन सुनने को यही मिलता है कि अतिथि शिक्षक स्थायी शिक्षकों की तरह जिम्मेदारी से अपना कार्य नहीं करते। हाल ही में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसबी) ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई कि अतिथि शिक्षकों की जब परीक्षा ली गई तो उनमें से 70 फीसद शिक्षक निम्नतम अंक भी हासिल नहीं कर पाए। क्या अब अनुमान लगाना इतना कठिन है कि जहां 22 हजार अतिथि शिक्षक विभिन्न स्कूलों में अपनी जो सेवा दे रहे हैं, उसकी गुणवत्ता किस स्तर की होगी। क्या ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे भाषा, गणित, विज्ञान आदि में यदि पिछड़ रहे हैं तो उनके पिछड़ने में इन शिक्षकों की सिखाने की शैली का हाथ नहीं होगा?

हमारे अतिथि शिक्षक किस प्रकार की शिक्षण प्रविधियों और तरीकों का प्रयोग कक्षा में कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को अतिथि व तदर्थ शिक्षकों के कंधे पर डालने की प्रक्रिया नब्बे के दशक में शुरू हो चुकी थी। देखते ही देखते इन शिक्षकों की संख्या देश के विभिन्न राज्यों में फैलती चली गई। केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों ने अतिथि और तदर्थ शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के समानांतर एक नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। इस प्रयास में काफी हद तक सफलता मिली। वहीं दूसरी ओर शिक्षाविदों, शिक्षक-प्रशिक्षकों आदि ने इस तदर्थवादी शिक्षक व्यवस्था का जमकर विरोध भी किया। तर्क-वितर्क की रोशनी में यह समझने-समझाने की कोशिश की गई कि प्राथमिक शिक्षा में अतिथि व तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति से बेहतर है स्थायी शिक्षकों को लगाया जाए। लेकिन शिक्षाविदों का विरोध बस कुछ खबरों की चौहद्दी तक ही सीमित रहा। उनके तर्क और स्थापनाएं सरकारी नीतियों को न तो प्रभावित कर पाए और न इसके लिए मजबूर कर पाए कि क्यों न अतिथि शिक्षकों की बजाय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में स्थायी नियुक्ति की जाए।

सरकारें भी लगातार दूसरे विकल्प पर काम करती रहीं, यानी शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के स्थान पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती पर अड़ी रहीं। अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर वर्ष 2009 में बना शिक्षा के मौलिक अधिकार (आरटीई) अधिनियम भी ज्यादा असर नहीं छोड़ पाया। वर्ष 2010 में बिहार सरकार ने लाखों अर्द्ध प्रशिक्षित एवं महज बीए और एमए पास को बतौर शिक्षक नियुक्तियां प्रदान की थीं। उत्तर प्रदेश में भी 2010 के बाद अखिलेश सरकार ने भी इसी तर्ज पर शिक्षकों की भर्ती की थी। हालांकि आरटीई एक्ट में स्पष्ट किया गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवाकालीन दो वर्ष के अंदर सरकार प्रशिक्षण प्रदान करेगी। कुछ राज्यों में अभी भी ऐसे अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं जिनके पास व्यावसायिक दक्षता एवं प्रशिक्षण नहीं है। ऐसे में किस प्रकार की शैक्षणिक गुणवत्ता की उम्मीद कर सकते हैं?

हर साल विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट बताती हैं कि हमारे बच्चे अपनी आयु और स्तर के अनुसार विषयी ज्ञान हासिल करने में पीछे हैं। इसके कारण बहुत हैं। लेकिन बड़ा कारण यह भी है कि हमने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा अतिथि शिक्षकों के भरोसे छोड़ दी है। हालांकि रिपोर्ट तो यह भी बताती हैं कि आज न केवल प्राथमिक शिक्षा, बल्कि तमाम विश्वविद्यालयों में भी स्थायी नियुक्तियां अब न के बराबर हैं।

हर साल विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की रिपोर्ट हमें बताती हैं कि हमारे बच्चे अपनी आयु और स्तर के अनुसार विषयी ज्ञान हासिल करने में पीछे हैं। इसके कारण बहुत हैं। लेकिन बड़ा कारण यह भी है कि हमने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा अतिथि शिक्षकों के भरोसे छोड़ दी है। हालांकि रिपोर्ट तो यह भी बताती हैं कि आज न केवल प्राथमिक शिक्षा, बल्कि तमाम विश्वविद्यालयों में भी स्थायी नियुक्तियां अब न के बराबर हो रही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी स्थायी नियुक्तियों के समानांतर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। ऐसे शिक्षकों की संख्या लाखों में है जो पिछले दस-पंद्रह साल से अतिथि शिक्षक के तौर पर ही अपनी सेवा दे रहे हैं। एक बात तो प्रमुखता से उभर कर यह सामने आती है कि सरकार को अस्थायी नियुक्तियों में कई जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल जाता है। वहीं अतिथि शिक्षकों को कभी भी बीच सत्र में भी बाहर का रास्ता दिखाना आसान होता है। जबकि इनसे भी शिक्षण संबंधी तमाम मांगों की पूर्ति की प्रतिबद्धता एवं जवाबदेही की उम्मीद की जाती है। ऐसे में स्थायी और अस्थायी कर्मी के बीच एक द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। इससे कैसे बाहर आया जाए, इस बाबत सरकारी नीतियां कोई खास मदद नहीं करतीं।

खासकर शिक्षण व्यवसाय से संबंध रखने वालों से शैक्षणिक ज्ञान और योग्यता की उम्मीद और अपेक्षा गलत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अध्यापन के लिए जा रहा है क्या उसकी शैक्षणिक समझ नवीन और व्यावसायिक अपेक्षाओं के अनुकूल है या नहीं, यह बेहद आवश्यक है। जहां तक शैक्षणिक ज्ञान का मसला है तो अतिथि शिक्षक भी बीएड-एमएड आदि पेशेवर ज्ञान एवं प्रशिक्षण हासिल कर शिक्षण व्यवसाय में आते हैं। यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जब वे कोर्स कर रहे होते हैं, तमाम तरह के शैक्षणिक दर्शन, मनोविज्ञान एवं इतिहास, वर्तमान की समझ साझा की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं जब वे बतौर शिक्षक कक्षा में आते हैं तब कुछ और व्यावसायिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए लगातार पढ़ते-लिखते रहना होता है। यदि हमारा शिक्षक अपनी शैक्षणिक ज्ञान और समझ को समय-समय पर पुनर्नवा नहीं करेगा तो वह कहीं न कहीं व्यावसायिक स्तर पर पिछड़ जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है, व्यावसायिक योग्यता व दक्षता।

शैक्षणिक ज्ञान तो किताबें पढ़ कर हासिल हो जाता है, लेकिन व्यावसायिक दक्षता अनुभव से ही आती है। जब हमारा शिक्षक कक्षा में खड़ा होता है तब ज्यादा चुनौतियां आती हैं। इनके निपटने के लिए कई बार किताबी ज्ञान और स्वविवेक का प्रयोग करना होता है। डीएसएसबी की रिपोर्ट इशारा कर रही है कि अतिथि शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता की कमी गहरी है। यदि पूरे देश की स्थिति पर नजर डालें तो स्थितियां संतोषजनक नहीं कही जा सकतीं। हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को जिन शिक्षकों के कंधे पर डाल कर निश्चिंत हो गए हैं, उसके नतीजे आने वाले वक्त में मिलेंगे। इस तल्ख हकीकत से हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं कि कक्षा में सीखने-सिखाने के विभिन्न स्तरों पर बच्चे पिछड़ रहे हैं। तमाम रिपोर्ट लगातार ताकीद कर रही हैं कि बच्चे विभिन्न विषयों की समझ में पीछे हैं। शिक्षक किन व्यावसायिक निष्कर्षों में पिछड़ रहे हैं, इसकी जांच करने की आवाज भी समय-समय पर उठती रही है।

गौरतलब है कि जब केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित की गईं तो उन परीक्षाओं में भी हमारे शिक्षक उम्मीद से कहीं ज्यादा फेल हुए थे। तब हमने जांच की कसौटियों एवं मानकों पर सवाल खड़े किए थे। क्या मानक और जांच की मंशा पर सवाल फेंक कर इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं कि शिक्षकों का भी सेवाकालीन मूल्यांकन होना चाहिए? इससे कम से कम शिक्षक अपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता का स्तर जरूर सुधारेगा।

■ कौशलेंद्र प्रपन्न
(वरिष्ठ पत्रकार)

जिले तूफान की जद में

भावनगर | तस्वीर गुजरात के पालीताणा की है। मंगलवार को शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में तेज गर्जना के साथ आसमानी बिजली गिरी। यह कुदरती कोप इतना तेज था कि इस पेड़ पर बिजली गिरते ही आग लग गई। उससे चिंगारियां निकलने लगीं।

सावधानी • 12वीं की स्थगित हुई परीक्षाओं को 9 जून से कराने की तैयारी

एक घंटे पहले विद्यार्थियों को करना होगी रिपोर्टिंग, एहतियातन हर केंद्र पर की जाएगी थर्मल स्कैनिंग

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थगित हुई 12वीं की परीक्षाओं को कराने की तैयारियां शुरू हो गई है। 9 से 15 जून तक यह परीक्षाएं होंगी। विद्यार्थियों को केंद्र पर एक घंटे पहले रिपोर्टिंग करना पड़ेगी ताकि उनकी ठीक से जांच होने के बाद बैठक व्यवस्था के आधार पर उन्हें सुरक्षित ढंग से परीक्षा केंद्र पर बैठाया जा सके।

उज्जैन जिले में 90 केंद्रों पर 19988 विद्यार्थियों की यह परीक्षा होगी। 9 से 15 जून तक चलने वाली इस परीक्षा में सुबह 9 से 12 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक की शिफ्ट में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। जिला शिक्षा अधिकारी रमा नाहटे ने बताया मंडल के निर्देशानुसार संक्रमण से बचाव के लिए पूरी एहतियात बरती जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग होगी। इसके लिए थर्मल स्कैनिंग मशीन खरीदने का काम शुरू हो गया है। इसकी राशि मंडल द्वारा दी जाएगी। वहीं हर केंद्र पर साबुन, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रहेगी। बैठक व्यवस्था इस प्रकार करने के निर्देश दिए हैं कि कम से कम 6 फीट का दायरा सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर रहे। एक-दो दिन में बैठक व्यवस्था पूरी करके केंद्रों पर निरीक्षण कर जायजा भी लिया जाएगा।

दौलतगंज स्कूल का केंद्र बदल माधव कॉलेज बनाया

शहर में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद परीक्षा कराने को लेकर विभाग को भी मशक्कत करना पड़ रही है। शाउमावि दौलतगंज भी परीक्षा का केंद्र था लेकिन यह स्कूल कंटेंनमेंट एरिया में आ चुका है, जिसके कारण जिला शिक्षा विभाग में इस केंद्र को बदलकर माधव कॉलेज में नया केंद्र बनाया है ताकि विद्यार्थियों को भी ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा शुरू होने के कुछ दिन पहले तक आवश्यकता पड़ने पर केंद्रों को बदला जा सकता है।

मंडल की जल्दी से विद्यार्थियों को होगी यह परेशानी

• कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सितंबर-अक्टूबर के बीच नए सत्र शुरू करने की घोषणा की जा चुकी है। वहीं सीबीएससी ने भी जुलाई में स्थगित परीक्षाएं रखी हैं लेकिन मंडल जून में ही परीक्षाएं करवा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के साथ पालक भी परेशान हैं। • केंद्र बदलने के लिए भी केवल उन विद्यार्थियों को राहत मिली है जो एक जिले से दूसरे जिले में हैं। वह संबंधित जिले में समीपस्थ केंद्र को चुन सकते हैं लेकिन अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूरदराज के इलाकों से आकर शहर में पढ़ते हैं।

निरीक्षण • लोक निर्माण विभाग ने माना इस शैक्षणिक सत्र के लिए उपयुक्त है केंद्रीय विद्यालय भवन

केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों को मिल सकेगा कक्षा पहली और 11वीं में प्रवेश

भास्कर संवाददाता | नेपानगर

अधिकारियों ने कहा- मरम्मत का काम पूरा कर भवन को ले सकता हैं उपयोग में

नगर के केंद्रीय विद्यालय की कक्षा पहली और 11वीं में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय भवन का निरीक्षण कर इसे उपयोगी बताते हुए प्रवेश को हरी झंडी दे दी है। विद्यालय में प्रवेश शुरू करने की मांग को लेकर पिछले दिनों पालकों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी आगे आए थे। पालकों ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और राज्य मंत्री को ई-मेल भेजा, वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए थे।

मंगलवार लोक निर्माण विभाग के एसडीओ सुमित पाटीदार और उपयंत्री सुधाकर चौधरी केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों ने यहां चल रहे मरम्मत कार्य के पूरा होने पर भवन को इस शैक्षणिक सत्र के लिए उपयुक्त माना है। उन्होंने बुधवार तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की बात भी कही है। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय की कक्षा पहली और 11वीं में प्रवेश का रास्ता खुल गया है। अब तक विद्यालय प्रबंधन भवन की खराब स्थिति के कारण प्रवेश देने से इनकार कर रहा था। अब जन सहयोग से भवन की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी भवन को उपयुक्त पाया है।

केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण करते लोक निर्माण विभाग के अधिकारी।

प्राचार्य ने ही भोपाल भेजी रिपोर्ट, लिखा- मरम्मत का काम पूरा हुआ

दरअसल यह सब स्थिति विद्यालय प्राचार्य अरविंदकुमार सिंह द्वारा भवन को अनुपयोगी बताने की रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय भेजने के कारण बनी थी। लेकिन अब उनकी ओर से ही लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर कहा गया है कि विद्यालय भवन की मरम्मत का काम पूरा करा लिया गया है। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहां निरीक्षण के लिए पहुंचे।इस दौरान पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण काटकर भी मौजूद थे।

पत्र पर हुआ था विरोध

पिछले दिनों विद्यालय प्रबंधन की ओर से पत्र जारी कर कहा गया था कि स्कूल भवन की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इस शैक्षणिक सत्र से कक्षा पहली और 11वीं में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद पालकों और जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर विरोध जताया था।

आगे क्या : केंद्रीय विद्यालय को नेपा मिल के साथ हुए करार के मुताबिक नया भवन बनाने के लिए अब तक जमीन नहीं मिली है। इस शैक्षणिक सत्र में तो कक्षा पहली और 11वीं में प्रवेश का रास्ता खुल गया है, लेकिन अगले सत्र से फिर यही परेशानी सामने आ सकती है। क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने भवन को सिर्फ इस सत्र के लिए उपयुक्त माना है। इसके लिए जरूरी है कि जनप्रतिनिधियों को जल्द नए भवन के लिए प्रयास करना होंगे।

भवन की मरम्मत का काम जनसहयोग से पूरा हो गया है। कल तक हम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। भवन इस शैक्षणिक सत्र के लिए उपयुक्त है।
-सुमित पाटीदार, एसडीओ लोक निर्माण विभाग बुरहानपुर

केंद्रीय मंत्री ने कलेक्टर से पूर्णता प्रमाण पत्र मंगाया

सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी पूर्णता प्रमाण पत्र दिल्ली बुलाया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा पूर्णता प्रमाण पत्र कलेक्टर के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भवन का निरीक्षण किया था, लेकिन तब जारी प्रमाण पत्र में उन्होंने शेष मरम्मत कार्य को पूरा करने की बात लिखी थी। इस पर आपत्ति आ गई। इसके बाद विद्यालय का बाकी मरम्मत काम भी पूरा कर लिया गया है। इसलिए अब यहां कक्षा पहली और 11वीं में प्रवेश का रास्ता खुल गया है।

नगर से पहले ही छिन चुकी सरकारी स्कूल की सुविधा

नगर से पहले ही सरकारी स्कूल की सुविधा छिन चुकी है। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय में भी प्रवेश नहीं मिलने का डर सभी को सता रहा था। पालकों और जनप्रतिनिधियों में इसको लेकर जबरदस्त आक्रोश था। नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान ने जनसहयोग से भवन की मरम्मत कराने की पहल की। साथ ही फोन पर सांसद नंदकुमारसिंह चौहान को स्थिति से अवगत कराया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मधु चौहान ने भी सांसद को लिखित में समस्या बताई। पालकों ने सांसद, केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल, केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखा और ई-मेल भेजा।

डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र 10 तक परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे

ग्वालियर| माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राएं 10 जून तक परीक्षा फॉर्म जमा कर पाएंगे। लॉकडाउन की वजह से छात्रों के परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे। परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाए जाने के बाद छात्र राहत में है। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इससे पहले परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख 30 मार्च से 5 अप्रैल तक घोषित की थी। बाद में लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। अब परीक्षा फॉर्म भरने की नई तारीख घोषित की गई हैं।

वहीं जीवाजी यूनिवर्सिटी ने अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत पीजी छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म घोषित करने की तारीखें घोषित कर दी हैं। एमजेएमसी चौथा सेमेस्टर, एमए, एमएससी, एमकॉम चौथा सेमेस्टर, पीजी डिप्लोमा इन योगा दूसरा सेमेस्टर, बीलिब, एमलिब दूसरा सेमेस्टर, एमबीए एचआरडी, एमबीएच एचए, एमबीए एफए, एमबीए ई-कॉमर्स, एमबीए बिजनेस इकॉनॉमिक्स, एमबीए टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन चौथे सेमेस्टर के छात्र नियमित परीक्षा शुल्क के साथ 9 जून तक और 500 रुपए लेट फीस के साथ 11 जून तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।

दस्तावेज में सुधार कर सकेंगे अभ्यर्थी

भोपाल. शिक्षक पद के अभ्यर्थी अपलोडेड दस्तावेज में 5 जून से सुधार कर सकेंगे। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पदों की सीधी भर्ती के तहत प्रावधिक चयन और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड करने, पूर्व में अपलोड किए दस्तावजों में हुई त्रुटि में सुधार करने अथवा सत्यापन के लिए पूर्व में चयनित जिले में परिवर्तन की सुविधा एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर क्रमश 5 से 12 जून तक तथा 10 से 24 जून तक उपलब्ध रहेगी।

शिक्षक भर्ती : 5 से 12 तक कर सकेंगे दस्तावेज अपलोड

भोपाल @ पत्रिका. स्कूल शिक्षा विभाग के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पदों की सीधी भर्ती के लिए जारी चयन सूची और वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज 5 से 12 जून तक अपलोड करना होगा। इन दस्तावेज में सुधार अथवा सत्यापन के लिए चयनित जिले में परिवर्तन 10 से 24 जून के बीच किया जा सकेगा। आवेदकों को एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।

बोर्ड परीक्षा : कंटेनमेंट जोन के लिए निर्देश जारी

छात्रों के प्रवेश-पत्र ही कोरोना पास के रूप में होंगे मान्य

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सतना. माध्यमिक शिक्षा मंडल की शेष रह गई हायर सेकंडरी व हायर सेकंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2020 की परीक्षाएं 9 से 16 जून तक कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसे लेकर जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने निर्देश जारी किए हैं कि कंटेनमेंट जोन में निवासरत छात्रों को परीक्षा केंद्र में आने-जाने के लिए छात्रों के प्रवेश-पत्र को ही पास के रूप में मान्य किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र भोपाल द्वारा कक्षा 12वीं के छात्रों को जो प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, उन्हीं को निवास स्थान से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए पास के रूप में मान्य किया जाएगा। छात्रों के साथ एक अभिभावक को साथ में आने-जाने की अनुमति दी गई है।

परीक्षा कक्ष में जाने से पहले होगी थर्मल स्क्रीनिंग

कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के क्रम में विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षाएं दो पाली सुबह 9 से 12 व दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होंगी। प्रथम पाली के विद्यार्थियों को सुबह 8 बजे व द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को 1 बजे तक केन्द्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। परीक्षा कक्ष में सुबह 8:45 व दोपहर 1:45 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर-पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न-पत्र दिए जाएंगे।

राजधानी के अभिभावकों को साइबर अपराधियों की ओर से मिल रही धमकियां

15 हजार दो नहीं तो खराब हो जाएगा बेटी का भविष्य

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. साइबर अपराधियों की नजर अब बोर्ड की परीक्षा दे चुके छात्र-छात्राओं सहित उनके अभिभावकों पर है। ये अपराधी विद्यार्थियों के नंबर बढ़वाने के लिए उनके अभिभावकों से सीधे सम्पर्क कर उन्हें बच्चों के परीक्षाओं में नंबर कम आने का झांसा देते हुए उन्हें पास कराने और नंबर बढ़ाने के तरीके बता रहे हैं।

ऐसा नहीं करने पर अभिभावकों को बच्चों को फेल कराने की धमकी दी जा रही है। ऐसे ही कई मामले राजधानी भोपाल में सामने आए हैं, जिनमें अभिभावकों को फोन कर बच्चों को फेल कराने की धमकी देते हुए साइबर अपराधियों ने सौदेबाजी करनी शुरू कर दी है। इससे अभिभावक सकते में हैं। इस मामले में अपराधी अपने को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल का कर्मचारी बताकर ठगी कर रहे हैं। अभिभावकों ने थाने में पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साथ ही रोहित नगर स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपसचिव एवं क्षेत्रीय अधिकारी को इस संबंध में शिकायत की है। अभिभावकों का कहना है कि यदि उनके बच्चों के रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी सीबीएसई बोर्ड की होगी।

केस एक

कटारा हिल्स निवासी एसआर वामनिया ने अपनी शिकायत में बताया कि मेरी पुत्री अंशिका वामनिया केंद्रीय विद्यालय क्रमांक तीन में कक्षा 10वीं की छात्रा है। जिसका अभी परीक्षा परिणाम नहीं आया है। वामनिया ने बताया कि मेरे पास राकेश राठौर नामक व्यक्ति द्वारा मोबाइल से 30 मई को कॉल कर कहा गया कि हम कम्प्यूटर में डाटा अपलोड कर रहे हैं। आपकी बेटी के गणित में बहुत कम नम्बर हैं, यदि आपको बढ़वाना है तो मुझे 15 हजार रुपए दे दो, मैं नंबर बढ़वा दूंगा। अगर आपने पैसे नहीं दिए, तो आपकी बेटी गणित में फेल हो जाएगी।

केस दो

नंदगांव बागमुगालिया निवासी एसके शर्मा ने बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि राकेश राठौर नामक व्यक्ति ने उनकी बेटी का कक्षा 10वीं का रिजल्ट खराब करने की धमकी दी है। शर्मा ने बताया कि मेरी पुत्री महक शर्मा कक्षा 10वीं की छात्रा है, जो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक तीन में अध्ययनरत है। मेरे पास 30 मई को दोपहर राकेश राठौर नामक व्यक्ति के मोबाइल नंबर से कॉल आया कि आपकी बेटी के गणित विषय में 28 नंबर आए हैं। आप मेरे बैंक एकाउंट में 15 हजार रुपए डाल दें तो आपकी बेटी के रिजल्ट सुधार दूंगा। यदि ऐसा नहीं किया तो बेटी का रिजल्ट खराब हो जाएगा।

कोई पैसे मांगे तो तत्काल पुलिस को दें सूचना

साइबर जालसाज अलग-अलग तरीके से ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति फोन कर धमकी दे रहा है या पैसे की मांग कर रहा है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें, जिससे आगे की कार्रवाई हो सके।

संदेश जैन, एएसपी, साइबर क्राइम